प्रताप सिंह

बनाम

प्रीतम सिंह और एक अन्य

19 अगस्त, 1969

[जे. सी. शाह, कार्यवाही मुख्य न्यायाधिपति, वी. रामास्वामी, ए. एन. ग्रोवर, न्यायाधिपतिगण]

मध्यस्थता अधिनियम, 1940- धारा 31(4)- का दायरा

अपीलकर्ता और प्रतिवादी तीन अलग-अलग स्थानों- मध्य प्रदेश के पिपलिया, बॉम्बे और नागपुर में तीन व्यवसाय चला रहे थे। साझेदारी व्यवसाय से संबंधित कुछ विवादों को मध्यस्थ के पास भेजा गया था, चार महीने के भीतर संदर्भ को पूरा करने में सक्षम नहीं होने पर, मध्यस्थ ने समय के विस्तार के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश, दिल्ली के पास आवेदन किया। आवेदन पर विचार करने के उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में आपत्ति को खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायाधीश, दिल्ली ने पंचाट पारित करने के लिए समय विस्तार दिया।

जब इस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण आवेदन दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था, तो प्रतिवादी ने कुछ राहतों के लिए मध्य प्रदेश में

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा दायर किया। इस बीच अपीलार्थी ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत मुकदमे पर रोक के लिए आवेदन किया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने संपत्तियों का रिसीवर नियुक्त किया। अपील में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए, यह एक ऐसा मामला था जिसमें दिल्ली में अधीनस्थ न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय किए बिना, रिसीवर की नियुक्ति के लिए आवेदन पोषणीय था।

इस न्यायालय में अपील में यह तर्क दिया गया था कि विवाद में या मध्यस्थ के समक्ष किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी भी अन्य संपत्ति के रिसीवर को नियुक्त करने के लिए न्यायालय के लिए खुला था और उस शक्ति की पुष्टि करके, सिविल न्यायालय की रिसीवर नियुक्त करने के शक्ति को मुकदमे से बाहर रखा गया था और इसलिए, रिसीवर की नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम एकमात्र न्यायालय दिल्ली में अधीनस्थ न्यायाधीश था, न कि मध्य प्रदेश में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत।

अपील खारिज करते हुए, अभिनिर्धारित किया:

आम तौर पर मध्यस्थ के समक्ष विवाद के विषय-वस्तु के संबंध में अंतरिम राहत देने के लिए पक्षकारो को उस अदालत का सहारा लेना होगा,

जहां निर्णय देने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया गया था। लेकिन समय विस्तार के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश, दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र के कारण सिविल कोर्ट विवाद में था जो मुकदमे से जब्त किया गया है वह उस संपत्ति को संरक्षित करने के लिए उचित आदेश देने का हकदार था जो मुकदमे की विषय-वस्तु है। [780 सी-डी]

इसलिए, मध्य प्रदेश में सिविल कोर्ट धारा के तहत दिल्ली-न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में सवाल उठने तक संपत्ति का रिसीवर नियुक्त करने में सक्षम था। रेफरेंस के आदेश से उत्पन्न होने वाले आवेदनों पर विचार करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 (4) को अंततः निर्धारित किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उस प्रश्न को निर्धारित करने के बाद, क़ानून की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए नियुक्त रिसीवर को दिल्ली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अधीन किया जा सकता है यदि यह माना जाता है कि दिल्ली कोर्ट के पास आवेदन पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है। [780-ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2321/1968

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ के सिविल विविध अपील संख्या 111 /1967 में निर्णय और आदेश दिनांकित 1 नवंबर, 1968 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ता की ओर से सी.आर. दफ्तरी और बी. दत्ता।

पी. सी. खन्ना, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

न्यायालय का निर्णय जे.सी. शाह, कार्यवाही मुख्य न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया- प्रताप सिंह, प्रीतम सिंह और दीवान सिंह तीन भाई हैं। प्रताप सिंह और प्रीतम सिंह ले तीन स्थानों पर साझेदारी में व्यापार किया गया- (1) मध्य प्रदेश में पिपलिया, जोरा स्लेट पेंसिल वर्क्स के नाम पर; (2) बम्बई, पार्टाप ब्रदर्स के नाम पर; और (3) नागपुर, नाइस टाइल्स और मार्बल के नाम पर, नागपुर: 18 दिसंबर, 1965 के एक समझौते के द्वारा प्रताप सिंह और प्रीतम सिंह के बीच साझेदारी व्यवसाय से संबंधित विवादों को उनके भाई दीवान सिंह की मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। मध्यस्थ ने संदर्भ में प्रवेश किया, लेकिन वह चार महीने के भीतर संदर्भ को पूरा करने में असमर्थ रहा। दीवान सिंह ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 के तहत अधीनस्थ न्यायाधीश, दिल्ली की अदालत में समय के विस्तार के लिए आवेदन किया। प्रीतम सिंह ने दिल्ली स्थित अधीनस्थ न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताई। अधीनस्थ न्यायाधीश ने आपत्ति को खारिज कर दिया और पंचाट देने के लिए समय बढ़ा दिया। आदेश के विरुद्ध दायर एक पुनरीक्षण आवेदन दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

इस बीच, प्रीतम सिंह ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मंदसौर की अदालत में प्रताप सिंह और प्रीतिपाल सिंह (प्रीतम सिंह के बहनोई) के खिलाफ जावरा स्लेट पेंसिल वर्क्स के संबंध में लेनदेन का हिसाब देने की डिक्री के लिए और रिसीवर की नियुक्ति हेतु एक याचिका दायर की। वादपत्र में संशोधन करके साझेदारी के विघटन का दावा भी किया गया। प्रताप सिंह ने मध्यस्थता अधिनियम 1940 की धारा 34 के तहत मुकदमे पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया और आवेदन मंजूर कर लिया गया। लेकिन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि पिपलिया में जावरा स्लेट पेंसिल वर्क्स की संपत्तियों के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया जाए। उस आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील की गई। उच्च न्यायालय का विचार था कि रिसीवर की नियुक्ति के लिए एक मामला बनाया गया था। न्यायालय ने आगे कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित कार्यवाही के संबंध में यह एक ऐसा मामला था जिसमें दिल्ली में अधीनस्थ न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय किए बिना, रिसीवर की नियुक्ति के लिए आवेदन विचारणीय था। उस आदेश के विरूद्ध विशेष अनुमति सहित यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

इस अपील में तर्क दिया गया एकमात्र प्रश्न अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मंदसौर के मुकदमे पर विचार करने और रिसीवर नियुक्त करने के अधिकार क्षेत्र के बारे में है। सबसे पहले प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दिया जा सकता है।

मध्यस्थता अधिनियम की अनुसूची के खंड 3 द्वारा मध्यस्थ को रेफरेंस दर्ज करने के चार महीने के भीतर पंचाट देना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 28 में प्रावधान है कि न्यायालय, यदि उचित समझे, पुरस्कार देने का समय समाप्त हो गया है या नहीं और पुरस्कार दिया गया है या नहीं, समय-समय पर पुरस्कार देने का समय बढ़ा सकता है, और अभिव्यक्ति "न्यायालय" को 2 (सी) में अर्थ "एक सिविल न्यायालय को रेफरेंस की विषय-वस्तु बनाने वाले प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र है यदि वह एक मुकदमे का विषय-वस्तु रहा हो, परिभाषित किया गया है, लेकिन अधिनियम की धारा 31 प्रदान करती है।

(1).....

(2).....

(3) मध्यस्थता कार्यवाहियो के संचालन के संबंध में सभी आवेदन या अन्यथा उस न्यायालय में की जाएगी जहां पुरस्कार दिया गया है, या दायर किया जा सकता है, और किसी अन्य न्यायालय में नहीं।

(4) इस अधनियम में अन्यत्र कुछ भी निहित होते हुए भी या उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में, जहां किसी भी संदर्भ में इस अधिनियम के तहत कोई आवेदन उस पर विचार करने के लिए सक्षम न्यायालय में किया गया है, उस न्यायालय के पास मध्यस्थता कार्यवाही और उस रेफरेंस से उत्पन्न होने वाले सभी बाद के आवेदनों पर अधिकार

क्षेत्र होगा और मध्यस्थता कार्यवाही उसी न्यायालय में की जाएगी, किसी अन्य न्यायालय में नहीं।

अधिनियम की धारा 34 किसी मुकदमे पर रोक लगाने का प्रावधान करती है। जहां तक यह भौतिक है, यह अधिनियमित होता है।

> "जहां मध्यस्थता समझौते का कोई भी पक्ष समझौते के किसी अन्य पक्ष के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही शुरू करता है" किसी भी मामले के संबंध में जिसे संदर्भित करने पर सहमति हुई है, ऐसी कानूनी कार्यवाही के लिए कोई भी पक्ष लिखित बयान दाखिल करने या कोई अन्य लेने से पहले किसी भी समय कर सकता है। कार्यवाही में कदम रखते हुए, कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए उस न्यायिक प्राधिकरण को आवेदन करें जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है; और यदि संतुष्ट है कि कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि मामले को मध्यस्थता समझौते के अनुसार क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए और आवेदन उस समय था जब कार्यवाही शुरू हुई थी, और अभी भी सभी आवश्यक चीजें करने के लिए तैयार और इच्छुक है। मध्यस्थता के उचित संचालन के लिए ऐसा प्राधिकारी कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दे सकता है।"

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मंदसौर के समक्ष लंबित मुकदमे पर रोक लगाने के लिए प्रताप सिंह द्वारा एक आवेदन दिया गया था और इसे मंजूर कर लिया गया था। लेकिन इससे मुकदमे की विषय वस्तु की सुरक्षा के लिए उचित आदेश पारित करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं रखा गया। रिसीवर की नियुक्ति के लिए आवेदन मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत मुकदमे पर रोक के आदेश के बावजूद भी दिया जा सकता है। लेकिन यह आग्रह किया गया कि विवाद में या मध्यस्थ के समक्ष किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी अन्य संपत्ति के रिसीवर को नियुक्त करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 41 में परिभाषित अनुसार यह अदालत के लिए खुला है, और उस शक्ति को प्रदान करके, रिसीवर नियुक्त करने के लिए एक मुकदमे में सिविल कोर्ट की शक्ति को बाहर रखा गया है। उस आधार पर यह आग्रह किया गया था कि रिसीवर की नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम एकमात्र न्यायालय दिल्ली में अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय था, न कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मंदसौर का न्यायालय। यह सच है कि पंचाट देने के लिए समय बढ़ाने के लिए एक आवेदन दिल्ली के अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में किया गया था और आम तौर पर पक्षकारो को पहले विवाद के विषय-वस्तु के संबंध में अंतरिम राहत के लिए उस मध्यस्थ अदालत का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन जब तक समय विस्तार के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए

अधीनस्थ न्यायाधीश, दिल्ली की अदालत का अधिकार क्षेत्र विवाद में था, तब तक सिविल कोर्ट, जो मुकदमे से संबंधित है, उस संपत्ति को संरक्षित करने के लिए उचित आदेश देने का हकदार था जो कि वाद विषय वस्तु है।

इसलिए हमारा विचार है कि मंदसौर में सिविल कोर्ट तब तक संपत्ति का रिसीवर नियुक्त करने में सक्षम था जब तक कि संदर्भ के आदेश से उत्पन्न होने वाले आवेदनों पर विचार करने के लिए धारा 31(4) के तहत दिल्ली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में सवाल अंतिम रूप से निर्धारित नहीं हो जाता। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उस प्रश्न का निर्धारण करने के बाद, क़ानून की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए नियुक्त रिसीवर को दिल्ली न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन किया जा सकता है, यदि यह माना जाता है कि दिल्ली न्यायालय के पास आवेदन पर विचार करने का क्षेत्राधिकार था।

यह आग्रह किया गया था कि मंदसौर में दायर मुकदमा केवल मैडबिस प्रदेश राज्य के भीतर पिपलिया में साझेदारी की संपत्ति से संबंधित है और बॉम्बे और नागपुर में संपत्तियों से संबंधित नहीं है और नियुक्ति के लिए आदेश प्राप्त करने की समीचीनता से रिसीवर प्रीतम सिंह, प्रताप सिंह को छोड़कर बंबई और नागपुर में संपत्तियों पर कब्ज़ा बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। हम इस स्तर पर यह तय नहीं कर सकते

कि जहां तक यह मुकदमा केवल पिपलिया में साझेदारी की संपत्ति से संबंधित है, यह सुनवाई योग्य है या नहीं। मध्यस्थता की कार्यवाही निस्संदेह साझेदारी की सभी संपत्तियों से संबंधित है और यदि प्रताप सिंह द्वारा तर्क दिया गया है, तो प्रताप सिंह को छोड़कर, प्रीतम सिंह, बॉम्बे और नागपुर में साझेदारी की संपत्तियों के कब्जे में बने हुए हैं और एक रिसीवर नियुक्त किया जाना यह उचित और न्यायसंगत है, उसका उपाय उस उद्देश्य के लिए उचित कार्यवाही शुरू करना और संपत्तियों का रिसीवर नियुक्त करने के लिए सक्षम अदालत में आवेदन करना है।

अपील असफल होने के कारण खारिज की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

पी. बी. आर.

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।